

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्वाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :- विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या: - 156/2024 प्रार्थना पत्र

GCMS No. - 2024/582

1. लीला पुत्री गोकल जी जाति रेगर निवासी लसडावन तह० निम्वाहेड़ा राज०
2. शम्भूलाल पिता पन्ना जी जाति रेगर निवासी लसडावन तह० निम्वाहेड़ा राज०
3. श्रीमती आरती पत्नी दुर्गेश जी गोदपुत्री बाबुलाल जी जाति रेगर निवासी लसडावन तह० निम्वाहेड़ा राज०

-प्रार्थीगण

बनाम

1. गोकल पिता पन्ना जी जाति रेगर निवासी लसडावन तह० निम्वाहेड़ा राज०
2. शोभालाल पिता किशनलाल जी जाति सालवी निवासी मेनार तहसील वल्लभ नगर, जिला उदयपुर राज०
3. राज० सरकार जरिये तहसीलदार निम्वाहेड़ा राज०
4. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयक कार्यालय, निम्वाहेड़ा तह० निम्वाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955

उपस्थित :-1-श्री ज्ञानचन्द्र धाकड - अधिवक्ता प्रार्थीगण
2-श्री राकेश भट्ट - अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01
3-श्री जगदीश चन्द्र मेनारिया -अधिवक्ता विपक्षी संख्या 02

:: निर्णय ::

दिनांक :- 20.09.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि मोजा लसडावन पटवार हल्का लसडावन की आराजी नम्बर 371 रकवा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 372 रकवा 0.8000 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 373 रकवा 0.0100 हैक्टेयर भूमि स्थित है।
2. उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के पिता व दादा जी पन्ना जी के समय की है तथा पन्ना जी के जीवनकाल में प्रार्थीया लीला के पिता गोकल जी, प्रार्थी शम्भूलाल एवं श्रीमती आरती के गोद पिता बाबुलाल जी शामिल रहते थे और परिवार में कर्ता पुरुष व बालिग होने से गोकल पिता पन्ना जी के नाम से उक्त आराजीयात आवंटित कराई जिसके पुराने आ०न० 208 रकवा 4 बिघा हैं, तथा उस समय गोकल, बाबु व शम्भू तीनों भाईयो ने आपस में उक्त आवंटित शुदा जमीन में 1/3-1/3 हक हिस्सा तीनों भाईयो का रहेगा तथा तीनों भाई अपने अपने हक हिस्से की जमीन पर स्वयं काबिज होकर काश्त करें, रहन करें, वय, बक्षीशा किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। तथा उक्त आराजी में कुंआ भी शामला खुदाया था उसमें भी तीनों भाईयो का समानहक हिस्सा रखा गया। जो कि सन 1984 में आपस में इकरारनामा बंटवारानामा लिखा गया है, उसी अनुसार मौके पर

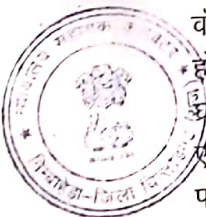


सहायक कलक्टर
निम्वाहेड़ा

1984 में आपस में इकरारनामा बंटवारानामा लिखा गया है, उसी अनुसार मौके पर काबिज चले आ रहे हैं। तथा प्रार्थी शम्भूलाल उक्त आराजी के 1/3 भाग पर एवं गोकल के 1/3 भाग पर गोकल एवं प्रार्थीया लीला काबिज है एवं बाबुलाल फौत होने से उसके 1/3 भाग पर उसकी गोद पुत्री प्रार्थीया आरती काबिज चली आ रही हैं।

3. विपक्षी सं० 1 की आयु 80 साल की होकर वृद्ध है और उनकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो गई है तथा वर्तमान में जमीनों की किमते बढ़ जाने से विपक्षी सं० 1 की नियत में बदलांति आ गई है और भू माफीयाओ के सिखावे में आकर विपक्षी सं० 1 ने उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात को विपक्षी सं० 2 शोभालाल को विक्रय कर विक्रय पत्र का पंजीयन दिनांक 08.07.2024 को करा दिया जबकि उक्त आराजीयात में प्रार्थी शम्भूलाल का 1/3 हिस्सा एवं प्रार्थीया आरती 1/3 हिस्सा अपने गोदपिता बाबुलाल से मिला हुआ है तथा प्रार्थीया लीला का 1/3 में से 1/2 हिस्सा अपने पिता गोकल के हिस्से में से जन्म से निहित है, इस प्रकार तीनों प्रार्थीगण का कुल 5/6 हिस्सा निहित है, इसलिये प्रार्थीगण की बगैर लिखित अनुमति के विपक्षी सं० 1 को उक्त सम्पूर्ण आराजीयात का रकबा विक्रय करने का अधिकार नहीं था इसलिये उक्त विक्रयपत्र प्रार्थीगण के हक अधिकारों के मुकाबले शून्य दस्तावेज है तथा उक्त आराजीयात का उचित प्रतिफल व कब्जे का आदान प्रदान नहीं किया गया इसलिए उक्त बिकाव बोगस व फर्जी है जो कि मात्र प्रार्थीगण को उनके जायज हक से वंचित करने की नियत से किया गया है।

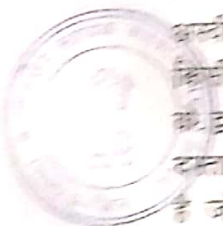
4. वर्णित आराजीयात प्रार्थी शम्भूलाल के शामिल शरीक रहते हुए परिवार में बड़ा भाई विपक्षी सं० 1 गोकल कर्ता खानदान होने से उक्त आराजीयात गोकल के नाम से आवंटित कराई लेकिन मौके पर गोकल व उसके दोनों भाई शम्भूलाल व बाबुलाल का समान रूप से 1/3-1/3 हक हिस्सा व अधिकाररखा गया तथा इस संबंध में दिनांक 16.11.1984 को स्टाम्प पर रूबरू गवाहान बंटवाडा विलेख निश्पादित किया गया और उसी अनुसार तीनों भाईयो ने उक्त आराजीयात को काबिज काश्त करने में अपनी पुरी जिन्दगी की मेहनत की कमाई लगा दी और कुंआ भी शामिल तौर से खुदवाया काबिल काश्त बनाया, जिसमें भी तीनों भाईयो का समान 1/3-1/3 हक हिस्सा रखा गया, इसके बावजूद भी विपक्षी सं० 1 ने सम्पूर्ण आराजीयात की विक्रय की रजिस्ट्री विपक्षी सं० 2 के नाम पर गुपचुप तरीके से करा दी है जो प्रार्थीगण के हितों के मुकाबले शून्य है। क्योंकि विपक्षी सं० 1 को अपने 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि 1/6 हिस्सा प्रार्थीया लीला बाई का एवं 1/6 हिस्सा विपक्षी सं० 1 का था और उसी हक हिस्से को ही हस्तांतरण करने का अधिकार था। इसलिये उक्त विक्रय पत्र प्रार्थीगण के हितों के मुकाबले नल एण्ड वॉर्ड है। मौके पर प्रार्थीगण अपने अपने हक हिस्से की आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं इसलिए प्रार्थीगण के नाम उक्त आराजीयात घोषित फरमाया जाना आवश्यक है तथा प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य बाय मिट्स एण्ड वाउण्डस बंटवाडा किया जाकर लगान की फांटनी की जावें तथा उक्त विक्रय पत्र में कब्जे का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ है, इसलिये उक्त दस्तावेज विधि अनुसार शून्य दस्तावेज होकर नल एण्ड वॉर्ड है जिसके आधार पर विपक्षी सं० 2 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।



सचिव कलक्टर
निम्बाहेड़ा

5. प्रार्थीनग ने दिनांक 16.07.2024 को विपक्षीनग से उक्त विक्रय पत्र खारिज कराने हेतु व आराजीयात प्रार्थीनग के नाम कराने हेतु कहा तो वो इंकार हो गये और प्रार्थीनग के कब्जे कास्त में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया और प्रार्थीनग का हक हिस्सा मानने से इंकार कर दिया और जायदाद खुद बुर्द करने की धमकीयां दी. इसलिये विपक्षीनग को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जावे कि वो प्रार्थीनग को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन बेदखल नहीं करें न करावें तथा आराजीयात के किसी भी मूनाग को जरिये रहन, बय, बर्खाश या अन्य तौर से खुर्द चुर्द हस्तांतरण नहीं करें न करावें तथा किसी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें न करावें तथा नौके कब्जे व रेकार्ड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करें न करावें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे प्रार्थीनग के हक अधिकार प्रभावित हो। यदि विपक्षीनग को पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थीनग को भारी अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो पायेगी तथा प्रार्थीनग का वाद पेश करना व्यर्थ हो जावेगा।

6. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीनगों को जरिये सन्मन तलब किया गया। विपक्षी क्रमांक 1 व 2 को आर से अधिवक्ता श्री जनार्दन चन्द्र मेनारिया ने अधिकार पत्र नय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदन पत्र की चरम संख्या 1 का जवाब इस प्रकार है कि उक्त चरम में वर्णित अनुसार वाद झुट व ननगदंत तथ्यों पर पेश किया है जो निश्चित रूप से खारिज होना ऐसी पुरी संभावना है। उक्त चरम में वर्णित तथ्य ननगदंत झुट तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार है तथा उक्त आराजीयात विपक्षी नं० 1 नोकल जी को आवंटित हुवा जमीन है, जिसमें प्रार्थीनग का कोई हक अधिकार किसी हैसियत से नहीं है तथा प्रार्थीनग का कोई संबंधकारी वादग्रस्त आराजी से कमी नहीं रहा है, उक्त आराजीयात विपक्षी नं० 1 नोकलजी को आवंटित हुई जिसके बाद से नोकलजी ही उक्त आराजीयात पर काबिज होकर कास्त करते आ रहे है, तथा किसी प्रकार से विपक्षी नं० 1 तथाकथित बटवारा नाना निष्पादित नहीं कराया न हो अन्य किसी नाईयों का व प्रार्थीनग का उक्त आराजीयात में कोई हक अधिकार निहित नहीं है। इस प्रकार उक्त चरम अस्वीकार है। विपक्षी नं० 1 नोकलजी को स्वर्जित आराजीयात होने से व अपने इलाज भरम पोषण हेतु तथ्य कर्ज अदायगी के लिए रुपया की आवश्यकता होने से विपक्षी नं० 1 द्वारा दिनांक 08/07/2024 को विपक्षी नं० 2 शोनालालन को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर कब्जा सुर्द कर दिया, तभी से विपक्षी नं० 2 उक्त आराजीयात पर काबिज होकर कास्त करता चला आ रहा है, तथा विपक्षी नं० 2 सदनाधिक कंता होकर मालिक स्वामी है। इस प्रकार उक्त चरम सन्पूर्ण रूप से अस्वीकार है। उक्त चरम में वर्णित तथ्य अस्वीकार है, उक्त आराजीयात तम विपक्षी नं० 1 का हक अधिकार निहित था अन्य विपक्षी का कोई हक अधिकार नहीं है न था, व किसी भी प्रकार से विपक्षी नं० 1 को द्वारा बटवारा निष्पादित नहीं कराया गया, यदि प्रार्थीनग द्वारा तथाकथित कोई दस्तावेज बटवारे बाबत पेश किया जाता है जो झुटा बनावटी कुट रचित दस्तावेज है जो विपक्षी नं० 1 व 2 पर बंधक कारो नहीं है, तथा उक्त आराजीयात में विपक्षी नं० 1 का हक अधिकार निहित था तथा विपक्षी नं० 1 द्वारा विपक्षी नं० 2 कंपक्ष से किया गया विक्रय पत्र विधि सन्मत दस्तावेज होने से वैध प्रभावी है। इसलिये



विपक्षी नं० 1
निवेदन

प्रार्थीगण उक्त दस्तावेज को किसी भी प्रकार से शुन्य व नल एंड वाईड कराने के अधिकारी नहीं हैं। इस प्रकार उक्त आराजी की कोई प्रार्थीगण के नाम की घोषणा कराने के अधिकारी नहीं है। उक्त चरण सम्पूर्ण रूप से अस्वीकार हैं। आवेदन पत्र की चरण संख्या 7 का जवाब इस प्रकार है कि उक्त चरण में वर्णित तथ्य अस्वीकार है, दिनांक 16/07/2024 को प्रार्थीगण ने कोई विक्रय पत्र खरीज कराने का कथन झुठा लिखा है जब प्रार्थीगण का उक्त वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक अधिकार नहीं है तथा विपक्षी नं० 1 की स्वअर्जित आराजीयात हैं तथा विपक्षी नं० 1 को अपनी स्वअर्जित आराजीयात को हर प्रकार से हस्तांतरण रहन विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, इसलिए प्रार्थीगण विपक्षी नं०1 व 2 को किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त होने योग्य है। आवेदन पत्र की चरण संख्या 8 का जवाब इस प्रकार है कि उक्त चरण में वर्णित तथ्य अस्वीकार है जब प्रार्थीगण का कोई कब्जा है ही नहीं तो सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। विपक्षी क्रमांक 3 व 4 ने जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब बन्द किया गया।

5. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया तथा विपक्षी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किए जाने का निवेदन किया।
6. वभिन्न न्यायिक दृष्टांतो का अध्ययन किया जो कि निम्नानुसार है:-
 - i. सरस्वती देवी बनाम महाराव ब्रजराज सिंह आर.आर.टी 2006-7 (सप)591
 - ii. मेघराज बनाम बाली बाई व अन्य आर.आर.टी 2009-10 (सप) 208
7. उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मददेनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है जिनका विश्लेषण इस प्रकार है-



- I. प्रथम दृष्टया मामला- हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात विपक्षी क्रमांक 1 गोकल की आवंटन शुदा आराजियात होने से अपने कर्ज अदायगी होने से विपक्षी नम्बर 2 शोभालाल को जरिए रजिस्टर विक्रय पत्र से दिनांक 08.07.20204 को विक्रय कर उक्त आराजियात का कब्जा सुपुर्द कर देने से उक्त आराजियात पर विपक्षी नम्बर 2 क्रय करने के बाद विपक्षी नम्बर 2 का बिज हाकिम काश्त कर रहा है तथा उक्त आराजियात पुश्तैनी आराजियात नहीं होने से व विपक्षी नम्बर 1 की स्वअर्जित आराजियात होने से हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत भी प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया उक्त आराजियात पर कोई भी हक अधिकार नियत नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सावित नहीं होता है।
- II. अपूरणीय क्षति- किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति

सहायक कलक्टर
निम्नाहेंडा

होना द्वितीय शर्त है। प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी अपना कब्जा साबित करने में असफल रहे हैं। अपूरणीय क्षति विपक्षी नम्बर 2 के क्रय होने से एवं विपक्षी नम्बर 1 की स्वर्जित आराजियात होने से प्रार्थीगण को विवादित आराजी पर कोई अपूरणीय क्षति नहीं होना साबित होता है।

III. सुविधा का संतुलन :- किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है।


9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते हैं। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि में विपक्षी नम्बर 1 की स्वर्जित भूमि होने से विक्रय करने का पूर्ण हक अधिकार था तथा विपक्षी नम्बर 2 द्वारा उक्त भूमि विपक्षी क्रमांक 1 से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर उपभोग उपयोग करने से प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुए हैं। अतः प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 01.08.2024 को खारिज किया जाना उचित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज योग्य है।

—:आदेश:—

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थी के पक्ष में साबित हो रहे हैं प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण और सुविधा का संतुलन भी नहीं पाया गया अतः प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नहीं करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद में तय होगा खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया




(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा